NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 03-05-2025

विषय सूची

भारत में उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना
बंदरगाह अर्थव्यवस्था भारत के विकास को गति देगी
"भारत में MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने" पर रिपोर्ट
आतंकवाद का वित्तपोषण
मस्तिष्क-कम्प्यूटर इंटरफेस (BCI) से लकवाग्रस्त लोगों में गतिशीलता संभव होगी

संक्षिप्त समाचार

तेलंगाना के पेद्दापल्ली में गुंडाराम शिलालेख
पश्चिमी विक्षोभ
माउंट मकालू
इनसाइडर ट्रेडिंग
घरेलू संस्थागत निवेशक (DIIs) FPIs से आगे
ब्लैक होल बम
पैंगोलिन
ऑपरेशन हॉक 2025
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार

भारत में उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना

संदर्भ

- ग्लोबल एलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप (GAME) और नीति आयोग ने भारत के कई राज्यों में जीवंत उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है।

मास एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में

- यह छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (SMEs) के व्यापक निर्माण को संदर्भित करता है, जो रोजगारों, आर्थिक वृद्धि और सामाजिक प्रभाव को उत्पन्न करते हैं।
- यह समावेशी व्यवसाय सृजन पर बल देता है, जिससे लाखों लोग रोजगार खोजने वाले की बजाय रोजगार देने वाले बन सकें, जबकि पारंपरिक उद्यमिता प्रायः उच्च-विकास स्टार्टअप पर केंद्रित होती है।

मास एंटरप्रेन्योरशिप के प्रमुख सिद्धांत

- **स्थानीय व्यवसाय वृद्धि को प्रोत्साहित करना:**विनिर्माण, खुदरा और सेवाओं सहित विविध क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्यमियों का समर्थन करता है।
  - सामुदायिक-संचालित उद्यमों को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **रोजगार सृजन और आर्थिक समावेशन:**विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का लक्ष्य।
  - महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए सशक्त बनाता है।
- **नीति और पारिस्थितिकी तंत्र समर्थन:**सरकार की नीतियों, वित्तीय पहुँच और मेंटरशिप कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है।
  - व्यवसायों, शैक्षिक संस्थानों और नीति निर्माताओं के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

GAME और नीति आयोग के बीच साझेदारी के उद्देश्य

- **स्थानीय उद्यमियों को सशक्त बनाना:**यह पहल उद्यमियों को समर्थन देने के लिए सरकारी एजेंसियों, कॉर्पोरेट्स, शैक्षिक संस्थानों, वित्तीय निकायों और सामुदायिक संगठनों को एक साथ लाने का लक्ष्य रखती है।
  - GAME और नीति आयोग उद्यमिता को एक आंदोलन में बदलने की योजना बना रहे हैं, जो आर्थिक वृद्धि और नौकरियों के निर्माण को प्रेरित करेगा, क्षेत्रीय चुनौतियों के अनुरूप स्थानीयकृत समाधान तैयार करके।
- **सिद्ध तरीकों को लागू करना:** पायलट साइटें (नागपुर, विशाखापत्तनम और उत्तर प्रदेश) GAME के स्थापित ढाँचे को अपनाने का लक्ष्य रखती हैं, जिसमें शामिल हैं:
  - स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसायों के लिए वित्तीय पहुँच।
  - उद्यमशीलता कौशल बढ़ाने के लिए क्षमता-निर्माण कार्यक्रम।
  - अनुकूल कारोबारी वातावरण बनाने के लिए नीति वकालत।
  - उद्यमियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक-संचालित पहल।
- **आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र बनाना:**अंतिम लक्ष्य ऐसे उद्यमशीलता हब विकसित करना है, जो व्यापक रोजगार के अवसर सृजित करना और भारत की आर्थिक दृढ़ता में योगदान देना।
- GAME ने विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से 3,00,000+ उद्यमियों की सहायता की है, जिससे उन्हें ऋण तक पहुँच, बाजार तक पहुँच और स्थान-आधारित हस्तक्षेपों का लाभ मिला है।

अन्य प्रमुख सरकारी पहलें जो उद्यमिता का समर्थन करती हैं

- **स्टार्टअप इंडिया पहल (2016):**यह नियमों को सरल बनाने, वित्तीय सहायता प्रदान करने और नवाचार को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है।

- इस पहल के तहत स्टार्टअप्स द्वारा 17.28 लाख से अधिक सृजित किये गए हैं।

- **अटल नवाचार मिशन (AIM):**यह नवाचार अवसंरचना निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें अटल टिंकरिंग लैब्स (ATL) और अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (AIC) का समर्थन शामिल है।
  - AIM 2.0, जिसे 2024 में मंजूरी मिली, ₹2,750 करोड़ के बजट के साथ भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करने का लक्ष्य रखता है।
- **स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (SISFS):**स्टार्टअप्स को प्रारंभिक चरण की फंडिंग प्रदान करता है, जिससे अवधारणा परीक्षण, प्रोटोटाइप विकास और बाज़ार में प्रवेश संभव हो सके।
  - दिसंबर 2024 तक, 2,622 स्टार्टअप्स को ₹467.75 करोड़ की फंडिंग से लाभ हुआ है।
- **स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (FFS) योजना (2016):**इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए घरेलू पूंजी तक पहुँच को बढ़ावा देना है, जिसमें ₹10,000 करोड़ का कोष शामिल है।

उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में चुनौतियाँ

- **वित्तीय पहुँच:**सरकारी समर्थन के बावजूद, कई स्टार्टअप्स वित्तीय अंतराल का सामना करते हैं, विशेष रूप से द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में।
- **नियामक जटिलता:**उद्यमियों को अनुपालन, कराधान और लाइसेंसिंग में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो व्यवसाय विकास को धीमा कर सकता है।
- **सीमित बाज़ार पहुँच:**स्टार्टअप्स को उद्योग से मजबूत जुड़ाव और वैश्विक बाज़ार एक्सपोजर की आवश्यकता होती है, ताकि वे प्रभावी रूप से आगे बढ़ सकें।

पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए सिफारिशें

- **वित्तीय समर्थन का विस्तार:**उभरते क्षेत्रों में स्टार्टअप्स के लिए वेंचर कैपिटल फंडिंग और क्रेडिट तक पहुँच बढ़ाना।
- **नियमों का सरलीकरण:** अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और उद्यमियों के लिए प्रशासनिक बाधाओं को कम करना।
- **बाज़ार संपर्क को बढ़ाना:**सार्वजनिक-निजी भागीदारी को मजबूत करना ताकि स्टार्टअप्स घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँच सकें।

Source: PIB

बंदरगाह अर्थव्यवस्था भारत के विकास को गति देगी

संदर्भ

- प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में विजिनजम इंटरनेशनल सीपोर्ट के उद्घाटन के दौरान कहा कि तटीय राज्य और बंदरगाह शहर विकसित भारत के प्रमुख विकास केंद्र बनेंगे।

बंदरगाह अर्थव्यवस्था क्या है?

- बंदरगाह अर्थव्यवस्था उन आर्थिक गतिविधियों और मूल्य को संदर्भित करती है जो बंदरगाहों के संचालन और विकास के माध्यम से उत्पन्न होते हैं।
- ये वैश्विक व्यापार और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में महत्त्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करते हैं।
- बंदरगाह वस्तुओं और लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाते हैं, निर्यात-आयात संचालन को सक्षम करते हैं, और जहाज निर्माण और मरम्मत का समर्थन करते हैं।

भारत की बंदरगाह अर्थव्यवस्था का इतिहास

- प्राचीन भारत में लोथल (गुजरात), मुज़िरिस (केरल), और अरिकमेडु (तमिलनाडु) जैसे बंदरगाह इंडो-रोमन, इंडो-ग्रीक और दक्षिण-पूर्व एशियाई व्यापार के प्रमुख केंद्र थे।
- मध्यकालीन काल में, सूरत, कालीकट और मछलीपट्टनम जैसे बंदरगाह अरबों, पारसियों, चीनी और यूरोपीय व्यापारियों के साथ व्यापार के प्रमुख केंद्र बने।
- हालाँकि, औपनिवेशिक काल में संसाधनों के दोहन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया, बजाय राष्ट्रीय विकास के।

भारत में बंदरगाह विकास की स्थिति

- भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह और 200 से अधिक गैर-प्रमुख बंदरगाह हैं।
- ये मिलकर भारत के कुल विदेशी व्यापार का लगभग 95% (मात्रा में) और 70% (मूल्य में) संभालते हैं।
- 2024-25 तक, भारत वैश्विक जहाज निर्माण में शीर्ष 20 देशों में शामिल है।
- भारत के दो बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) और मुंद्रा पोर्ट, विश्व स्तर पर शीर्ष 30 में शामिल हैं।
- विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) 2023 के अनुसार, भारत ने अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में वैश्विक रैंकिंग में 22वें स्थान तक बढ़त प्राप्त की और लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स स्कोर में कुल 38वें स्थान पर रहा।
- विजिनजम सीपोर्ट भारत का प्रथम समर्पित ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है, जिसका उद्देश्य विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता कम करना है, क्योंकि वर्तमान में भारत के 75% ट्रांसशिपमेंट विदेशों में होता है।
- सागरमाला पहल के तहत कोच्चि में एक जहाज निर्माण और मरम्मत क्लस्टर विकसित किया जा रहा है।

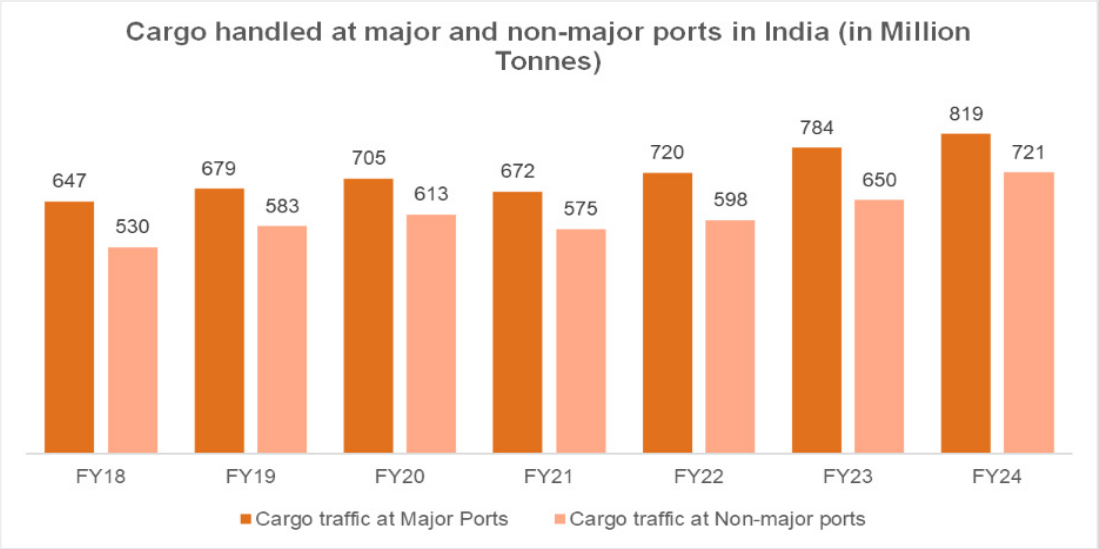

सुदृढ़ बंदरगाह अर्थव्यवस्था के लाभ

- **भू-रणनीतिक मूल्य:** बंदरगाह भारत के समुद्री प्रभाव को बढ़ाते हैं और SAGAR (सुरक्षा और क्षेत्र में सभी के लिए विकास) तथा प्रोजेक्ट मौसमी जैसी पहलों का समर्थन करते हैं।
- **क्षेत्रीय विकास:** बंदरगाह आधारित औद्योगिक क्षेत्र बुनियादी ढाँचे के विकास को उत्प्रेरित करते हैं और अंतर्देशीय क्षेत्रों में निजी निवेश को आकर्षित करते हैं।
- **पर्यावरणीय दक्षता:** सुनियोजित बंदरगाह कार्बन उत्सर्जन को कम करते हैं, टर्नअराउंड टाइम में सुधार लाते हैं, और रेलवे/अंतर्देशीय जलमार्गों की ओर मोडल शिफ्ट को सुविधाजनक बनाते हैं।
  - *टर्नअराउंड टाइम* वह समय है जो एक जहाज बंदरगाह पर आगमन से प्रस्थान तक व्यतीत करता है।
  - *अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT)* प्रति टन-किलोमीटर सड़क परिवहन की तुलना में 50% कम CO_2 उत्सर्जित करता है।
- **रोजगार सृजन:** बंदरगाह सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और सहायक क्षेत्रों में लाखों रोजगारों का समर्थन करते हैं।

चुनौतियाँ

- **उच्च लॉजिस्टिक्स लागत:** भारत की लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 13-14% है, जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यह 8-9% है।
- **विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता:** प्रमुख ट्रांसशिपमेंट गतिविधियाँ घरेलू गहरे जल की क्षमता की कमी के कारण कोलंबो, सिंगापुर और पोर्ट क्लांग पर निर्भर हैं।

- **बंदरगाह भीड़, प्रक्रियात्मक अक्षमताएँ और डिजिटलीकरण की कमी:** इन कारणों से देरी होती है, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी आती है।
- **पर्यावरणीय चिंताएँ:** बंदरगाह निर्माण और ड्रेजिंग तटीय पारिस्थितिक तंत्र और समुद्री जैव विविधता को क्षति पहुँचाते हैं।

सरकारी पहलें

- **सागरमाला कार्यक्रम:** यह लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए बंदरगाह आधुनिकीकरण, बंदरगाह-आधारित औद्योगीकरण और बेहतर अंतर्देशीय संपर्क पर केंद्रित है।
- **समुद्री भारत दृष्टि 2030:** यह भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ₹3 लाख करोड़ के लक्षित निवेश के साथ तैयार किया गया है, जिससे माल ढुलाई क्षमता 2,500 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक हो सके।
- **नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल (मरीन):** इसे एक एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में विकसित किया जा रहा है जहां सभी समुद्री हितधारकों को सुविधाजनक और तेज़ सेवाओं के लिए जोड़ा जाएगा।
- **₹25,000 करोड़ का समुद्री विकास कोष (MDF) की स्थापना:** यह कोष इस क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेशों को समर्थन देने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें सरकार 49% योगदान देगी और शेष 51% निवेश बंदरगाहों और निजी क्षेत्र से एकत्रित किया जाएगा।
- **पीएम गति शक्ति योजना:** यह बहु-मॉडल लॉजिस्टिक्स दक्षता को सुधारने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अवसंरचना योजना को एकीकृत करती है।

आगे की राह

- **हरित बंदरगाह विकसित करना:** पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए *शोर पावर*, *LNG बंकरिंग*, और *सस्टेनेबल ड्रेजिंग* में निवेश करना।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी:** *पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP)* बुनियादी ढाँचे के उन्नयन को तेज कर सकती है और सेवा गुणवत्ता में सुधार कर सकती है।
- **रणनीतिक भूगोल का लाभ उठाना:** भारत को प्रमुख वैश्विक व्यापार मार्गों के पास अपने स्थान का अधिकतम उपयोग करना चाहिए ताकि वह एक वैश्विक ट्रांसशिपमेंट और लॉजिस्टिक्स हब बन सके।

Source: TH

"भारत में MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने" पर रिपोर्ट

समाचार में

- नीति आयोग ने भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार पर एक रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट के बारे में

- इसे नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान (IFC) के सहयोग से तैयार किया है।
- इसका उद्देश्य वित्तपोषण, कौशल, नवाचार और बाजार पहुँच में व्यवस्थित सुधारों के माध्यम से भारत के MSMEs की क्षमता को अनलॉक करना है।
- यह कपड़ा, रसायन, मोटर वाहन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में वित्तपोषण, कौशल, नवाचार और बाजार पहुँच में चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।

भारत का MSMEs क्षेत्र

- यह भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख चालक है, जिसमें 5.93 करोड़ पंजीकृत उद्यम 25 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं।

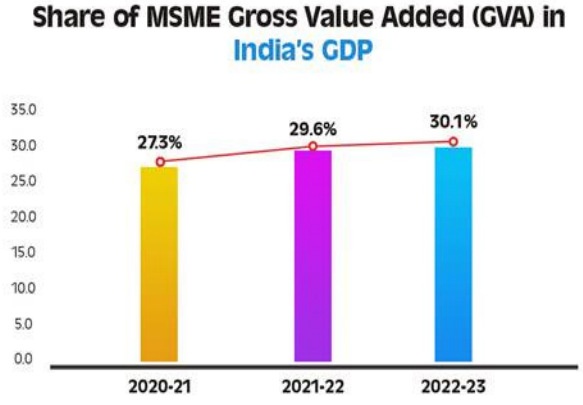

- 2023-24 में, MSMEs से संबंधित उत्पादों ने भारत के कुल निर्यात में 45.73% का योगदान दिया।

- हाल के वर्षों में, MSMEs क्षेत्र ने उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित किया है, देश के सकल मूल्य वर्धित में इसकी हिस्सेदारी 2020-21 में 27.3% से बढ़कर 2021-22 में 29.6% और 2022-23 में 30.1% हो गई है, जो राष्ट्रीय आर्थिक उत्पादन में इसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

- केंद्रीय बजट 2025-26 में MSMEs क्षेत्र को मजबूत करने के उपाय शामिल हैं, जैसे कि बढ़ी हुई ऋण पहुँच, प्रथम बार उद्यमियों के लिए समर्थन और श्रम-गहन उद्योगों को बढ़ावा देना।
- MSMEs के लिए वर्गीकरण मानदंड संशोधित किए गए हैं, निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना बढ़ाया गया है। इससे दक्षता, तकनीकी अपनाने और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

Rs. in Crore	Investment		Turnover	
	Current	Revised	Current	Revised
Micro Enterprises	1	2.5	5	10
Small Enterprises	10	25	50	100
Medium Enterprises	50	125	250	500

हालिया रिपोर्ट में उजागर की गई चुनौतियाँ

- हालाँकि, 2020 और 2024 के बीच, MSMEs की औपचारिक ऋण तक पहुँच में सुधार हुआ (सूक्ष्म और लघु उद्यम 14% से 20% तक, मध्यम उद्यम 4% से 9% तक), हालाँकि, MSMEs ऋण की 81% माँग पूरी नहीं हुई है, जिसमें अनुमानित 80 लाख करोड़ रुपये का अंतर है।
- क्रेडिट गारंटी फंड (CGTMSE) का विस्तार हुआ है, लेकिन अभी भी इसकी सीमाएँ हैं।
- कई MSMEs श्रमिकों के पास औपचारिक व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव है, जिससे उत्पादकता और मापनीयता में बाधा आती है।
- MSMEs का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा अनुसंधान एवं विकास, गुणवत्ता सुधार और नवाचार में भी कम निवेश करता है।
- अविश्वसनीय विद्युत सेवा, कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी और उच्च कार्यान्वयन लागत के कारण MSMEs को आधुनिक तकनीकों को अपनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- तकनीकी प्रगति का समर्थन करने वाली राज्य सरकार की योजनाएँ अक्सर कम जागरूकता के कारण दुर्गम होती हैं।
- कई MSMEs समर्थन नीतियों के बावजूद, उनकी प्रभावशीलता कम जागरूकता और खराब कार्यान्वयन के कारण सीमित है।

सुझाव और आगे की राह

- भारत के MSMEs लक्षित हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करके, मजबूत संस्थागत सहयोग का निर्माण करके और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर सतत आर्थिक विकास के प्रमुख चालक बन सकते हैं।
- रिपोर्ट में डिजिटल मार्केटिंग प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं के साथ साझेदारी और प्रत्यक्ष बाजार संपर्कों के लिए प्लेटफॉर्म बनाने के माध्यम से MSMEs के लिए बेहतर समर्थन की माँग की गई है, विशेषकर भारत के पूर्वोत्तर और पूर्वी बेल्ट जैसे उच्च विकास क्षमता वाले क्षेत्रों में।
- इसमें राज्य स्तर पर एक मजबूत, अनुकूली और क्लस्टर-आधारित नीति ढाँचे की माँग की गई है जो नवाचार को बढ़ावा दे, प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाए और MSMEs को समावेशी आर्थिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाए।

Source :PIB

आतंकवाद का वित्तपोषण

समाचार में

- भारत ने आतंक वित्तपोषण से निपटने के प्रयासों को तीव्र कर दिया है और आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देने के लिए धन के दुरुपयोग को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है।

समाचार के बारे में अधिक जानकारी

- भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (ADB) जैसी संस्थाओं से पाकिस्तान को दी जा रही वित्तीय सहायता की समीक्षा करने का आग्रह कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास निधि आतंक वित्तपोषण की ओर मोड़ी न जाए।
- भारत पाकिस्तान को फिर से *फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF)* की ग्रे सूची में डालने का समर्थ कर रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके वित्तीय तंत्र की कठोर निगरानी की जाए ताकि आतंक वित्तपोषण को रोका जा सके।

आतंक वित्तपोषण

- **परिभाषा:** आतंक वित्तपोषण उन व्यक्तियों या संगठनों को धन या वित्तीय सहायता प्रदान करने को संदर्भित करता है जो आतंकवाद में संलग्न हैं। यह धन वैध और अवैध दोनों स्रोतों से उत्पन्न हो सकता है और इसे भर्ती, प्रशिक्षण और हमलों को अंजाम देने जैसी आतंकवादी गतिविधियों को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है।
- **आतंक वित्तपोषण के प्रमुख स्रोत:**
  - **हवाला लेनदेन:** धन के भौतिक प्रवाह के बिना धन हस्तांतरण की एक अनौपचारिक विधि, जिसे प्रायः आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
  - **नकली मुद्रा:** नकली मुद्रा का प्रसार अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है और आतंकवादी अभियानों के लिए अचिह्नित धन प्रदान करता है।
  - **मादक पदार्थों की तस्करी:** अवैध मादक पदार्थों का व्यापार आतंकवादी समूहों के लिए एक महत्त्वपूर्ण राजस्व स्रोत के रूप में कार्य करता है।
  - **जबरन वसूली और अपहरण:** आतंकवादी संगठन व्यक्तियों और व्यवसायों से धन उगाहने के लिए जबरन वसूली और अपहरण में संलग्न होते हैं।
  - **चैरिटेबल संगठन और एनजीओ:** कुछ संस्थाओं का उपयोग धन संग्रह और आतंकवादी गतिविधियों की ओर उसके प्रवाह के लिए किया जाता है।

आतंक वित्तपोषण से निपटने में चुनौतियाँ

- **जटिल वित्तीय नेटवर्क:** आतंकवादी समूह उन्नत और विकेंद्रीकृत वित्तीय तंत्र का उपयोग करते हैं, जिससे उनका पता लगाना और बाधित करना मुश्किल हो जाता है।
- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग की कमी:** राष्ट्रों के बीच अपर्याप्त सहयोग वैश्विक स्तर पर आतंक वित्तपोषण से लड़ने की क्षमता को बाधित करता है।
- **कानूनी और नियामक खामियाँ:** विभिन्न देशों के कानूनी ढाँचे और प्रवर्तन क्षमताओं में असंगतियाँ आतंकवादियों को लाभ उठाने का अवसर प्रदान करती हैं।
- **प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग:** क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल भुगतान प्रणालियों के बढ़ते उपयोग से लेनदेन अज्ञात रह सकता है, जिससे यह ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है।

भारत द्वारा आतंक वित्तपोषण से निपटने के उपाय

- **विधायी ढाँचा:**
  - **गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA):** अधिकारियों को व्यक्तियों और संगठनों को आतंकवादी घोषित करने और उनकी संपत्तियों को जब्त करने की शक्ति देता है।
  - **धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA):** धन शोधन में शामिल संपत्तियों को जब्त करने का प्रावधान करता है।
- **संस्थागत तंत्र:**
  - **वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND):** संदिग्ध वित्तीय लेन-देन का विश्लेषण करती है और प्रवर्तन एजेंसियों को जानकारी प्रदान करती है।
  - **राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA):** आतंकवाद और इसके वित्तपोषण से संबंधित अपराधों की जांच और अभियोजन करती है।

- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:**
- भारत FATF और *नो मनी फॉर टेरर* (NMFT) जैसे वैश्विक मंचों में सक्रिय भागीदारी करता है ताकि अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाया जा सके।
- **तकनीकी उन्नति:**
  - सुरक्षा एजेंसियों के बीच वास्तविक समय में जानकारी साझा करने की सुविधा के लिए **राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (NATGRID)** को लागू किया जा रहा है।

Source: TH

मस्तिष्क-कम्प्यूटर इंटरफेस (BCI) से लकवाग्रस्त लोगों में गतिशीलता संभव होगी

संदर्भ

- कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्त्ताओं ने एक नया *ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCI)* विकसित किया है जो लकवाग्रस्त लोगों के लिए गति सक्षम करता है।

ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCI) क्या है?

- *ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस* मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि और बाहरी उपकरण के बीच एक सीधा संचार मार्ग है।
- सामान्यतः, *BCI* मानव संज्ञानात्मक या संवेदी-मोटर कार्यों की सहायता, वृद्धि या मरम्मत के लिए उपयोग किए जाते हैं।
- इस मामले में, *BCI* मस्तिष्क के मोटर कॉर्टेक्स—जो गति के लिए जिम्मेदार क्षेत्र है—से संकेत रिकॉर्ड करता है और उन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके रोबोटिक अंगों को संचालित करने के लिए डिकोड करता है।

BCI के प्रकार

- **इनवेसिव BCI:**
  - इन उपकरणों को मस्तिष्क में शल्यचिकित्सात्मक रूप से प्रत्यारोपित किया जाता है ताकि वे सीधे तंत्रिका तंत्र के साथ संपर्क कर सकें, जिससे मस्तिष्क एवं बाहरी उपकरणों के बीच संचार और नियंत्रण सक्षम हो सके।
  - यह सबसे सटीक संकेत प्रदान करता है; लकवे या *लॉक्ड-इन सिंड्रोम* के मामलों में उपयोग किया जाता है।
  - *उदाहरण: Neuralink's Blindsight*
- **आंशिक रूप से इनवेसिव BCI:**
  - ये उपकरण खोपड़ी के भीतर प्रत्यारोपित किए जाते हैं लेकिन मस्तिष्क के बाहर, आमतौर पर *ड्यूरा मेटर* पर स्थित होते हैं, जो मस्तिष्क को घेरने वाली एक झिल्ली होती है।
  - ये *इलेक्ट्रोकॉर्टिकोग्राफी (ECoG)* जैसी तकनीकों का उपयोग करके मस्तिष्क की सतह से विद्युत संकेत रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
- **नॉन-इनवेसिव BCI:**
  - ये ऐसे सिस्टम हैं जो उपयोगकर्त्ताओं को अपने विचारों के माध्यम से बाहरी उपकरणों (जैसे कंप्यूटर या रोबोट) के साथ बातचीत करने की अनुमति देते हैं, बिना सर्जरी की आवश्यकता के।
  - ये आमतौर पर *EEG इलेक्ट्रोड* जैसे बाहरी सेंसर का उपयोग करके मस्तिष्क संकेतों का पता लगाते हैं, जिससे वे इनवेसिव *BCI* की तुलना में अधिक सुरक्षित और सुलभ होते हैं।

BCI के अनुप्रयोग

- **चिकित्सा और पुनर्वास:**
  - **सहायक उपकरण:** *BCI* लकवाग्रस्त लोगों को व्हीलचेयर, रोबोटिक भुजा या कंप्यूटर कर्सर को नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं।
  - **न्यूरो-रिहैबिलिटेशन:** *BCI* के माध्यम से मस्तिष्क मार्गों को प्रशिक्षित करके *स्ट्रोक* के बाद मोटर रिकवरी की सुविधा प्रदान करता है।
  - **कृत्रिम अंग नियंत्रण:** मस्तिष्क संकेतों के माध्यम से संचालित कृत्रिम अंग।
- **शिक्षा और प्रशिक्षण:**
  - **ध्यान मॉनिटरिंग:** कक्षा में छात्र की सहभागिता को ट्रैक करने के लिए।

- **कौशल विकास:** जटिल कार्य सीखते समय ध्यान या मस्तिष्क गतिविधि पर प्रतिक्रिया प्रदान करना।

- **उद्योग और स्वचालन:**
  - **मानव-रोबोट इंटरैक्शन में BCI:** कारखानों में सहयोगी रोबोट को बेहतर बनाने के लिए।
  - **खतरनाक कार्यों में हैंड्स-फ्री नियंत्रण:** खनिकों या *रासायनिक संयंत्र* श्रमिकों के लिए, जहां हाथ व्यस्त रहते हैं।

BCI से संबंधित चिंताएँ

- **गोपनीयता:** *BCI* के माध्यम से एकत्र किए गए न्यूरल डेटा के दुरुपयोग का महत्त्वपूर्ण जोखिम है, क्योंकि ये सिस्टम संभावित रूप से व्यक्तियों के संवेदनशील विचारों, इरादों या भावनाओं तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं।
- **डिजिटल विभाजन:** *BCI* प्रणालियों की उच्च लागत और तकनीकी जटिलता डिजिटल विभाजन को व्यापक बना सकती है, जिससे हाशिए पर रहने वाले समूह इन जीवन-परिवर्तनकारी नवाचारों तक पहुँच से वंचित रह सकते हैं।
- **मानसिक स्वायत्तता:** यह चिंता बनी हुई है कि *BCI* के लंबे समय तक उपयोग से मस्तिष्क का कार्य प्रभावित हो सकता है या व्यक्ति की स्वतंत्रता की भावना कम हो सकती है, जिससे मानसिक स्वायत्तता और पहचान को लेकर सवाल उठते हैं।

आगे की राह

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि *BCI* का लाभ जनसामान्य, विशेष रूप से विकलांग लोगों तक पहुँचे, कम लागत वाले, स्केलेबल समाधान विकसित करना आवश्यक है।
- *पब्लिक-प्राइवेट* भागीदारी और *स्टार्टअप्स* प्रयोगशाला में विकसित नवाचारों को वास्तविक विश्व के अनुप्रयोगों में बदलने में सहायता कर सकते हैं।
- आगे शैक्षिक कार्यक्रमों और पेशेवर प्रमाणपत्र स्थापित करके इस उभरते क्षेत्र में एक कुशल कार्यबल का निर्माण किया जा सकता है।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

तेलंगाना के पेद्दापल्ली में गुंडाराम शिलालेख

प्रसंग

- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने तेलंगाना के पेद्दापल्ली के गुंडाराम रिजर्व फ़ॉरेस्ट में 11 नए शिलालेखों को प्रलेखित किया है।

मुख्य खोज

- ये शिलालेख *ईसा पूर्व पहली शताब्दी* से लेकर *ईसा पूर्व छठी शताब्दी* के बीच के हैं और *सातवाहन काल* तथा *दक्षिण भारत के प्रारंभिक सांस्कृतिक-राजनीतिक परिदृश्य* की महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।
- **लिपि और भाषा:** शिलालेख *प्रारंभिक ब्राह्मी लिपि* और *प्राकृत भाषा* में हैं।
- **शिलालेख 1:** *हरितिपुत्र* वंश के एक व्यक्ति (जो *चुटु वंश* से जुड़ा था) ने *बौद्ध भिक्षुओं* के लिए एक गुफा का उत्खनन किया था।
  - इसमें *कुमार हकुसिरी*, जो एक *सातवाहन राजकुमार* थे, के साथ मित्रता का उल्लेख किया गया है।
- **शिलालेख 2:** यह *त्रिशूल* और *डमरू* से प्रारंभ होता है, जो आमतौर पर *शैव धर्म* से संबंधित धार्मिक प्रतीक हैं।
  - इसमें उल्लेख है कि *पहाड़ी के पूर्वी भाग की भूमि सिरी देवरणा* के स्वामित्व में थी, जो एक *महातलवार* (उच्च पदस्थ अधिकारी) थे।

सातवाहन काल

- **समय अवधि:** प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व - तीसरी शताब्दी ई.पू.
- **राजधानी:** प्रतिष्ठान (महाराष्ट्र में आधुनिक पैठण)।
- उन्होंने दक्कन क्षेत्र पर शासन किया, जिसमें आधुनिक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्से शामिल हैं।
- इस राजवंश की स्थापना सिमुक ने की थी, जिन्होंने सातवाहन शासन की शुरुआती नींव रखी।
  - हालाँकि, गौतमीपुत्र सातकर्णी के शासनकाल में सातवाहन अपने चरम पर पहुँच गए।

Source: TH

पश्चिमी विक्षोभ

समाचार में

- उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी भारत में भारी वर्षा का कारण बनी नई *पश्चिमी विक्षोभ* प्रणाली।

पश्चिमी विक्षोभ के बारे में

- *पश्चिमी विक्षोभ* वे चक्रवातीय तूफ़ान हैं जो भूमि पर विकसित होते हैं।
- इन्हें *मध्य अक्षांश* या *अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात* कहा जाता है, क्योंकि इनका निर्माण मध्य और उच्च अक्षांशों में होता है।
- ये मुख्य रूप से *भूमध्यसागरीय क्षेत्र* में उत्पन्न होते हैं, जहाँ *उष्णकटिबंधीय उष्ण वायु* और *उत्तरी ध्रुवीय शीत वायु* के मिश्रण से *तापमान प्रवणता* बनती है।
- ये *भूमध्यसागर*, *काला सागर* और *कैस्पियन सागर* से आर्द्रता एकत्र करते हैं और *ईरान* एवं *अफगानिस्तान* से होकर पश्चिमी हिमालय तक पहुँचते हैं।
- हालाँकि ये *तूफ़ानी प्रणालियाँ* पूरे वर्ष होती हैं, लेकिन *उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम* की दिशा के कारण ये मुख्य रूप से *दिसंबर से अप्रैल* के बीच भारत में पहुँचती हैं।

भारत में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव

- *रबी फसलों* को वर्षा उपलब्ध कराकर और नदी प्रवाह बनाए रखकर समर्थन देते हैं।
- हालाँकि, अनियमित मौसम पैटर्न *रबी फसलों की पैदावार* को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
- भारत की *जलवायु और पर्यावरण* पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं, जो न केवल *मौसम प्रणाली* बल्कि देश की *खाद्य और जल सुरक्षा* को भी प्रभावित करते हैं।

Source: IE

माउंट मकालू

समाचार में

- भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (*ITBP*) ने नेपाल में स्थित *माउंट मकालू (8,485 मीटर)* पर अपनी पहली दोहरी *शिखर अभियान* के दौरान सफलतापूर्वक चढ़ाई की। यह अभियान *माउंट मकालू* और *माउंट अन्नपूर्णा* दोनों के लिए आयोजित किया गया था।

माउंट मकालू

- यह *खुम्बु क्षेत्र* में *एवरेस्ट से 20 किमी* पूर्व स्थित है और विश्व का *पाँचवाँ सबसे ऊँचा पर्वत* है।
- यह *मकालू बारुन राष्ट्रीय उद्यान* में स्थित है और अपनी *संपूर्ण पिरामिड आकृति* और *चार तीव्र पहाड़ी धारों* के लिए प्रसिद्ध है।
- इस पर्वत के *उत्तर में तिब्बत* स्थित है, और इसके दो प्रमुख *उपग्रह चोटियाँ* हैं:
  - **कांगचुंगत्से**, जिसे *मकालू II* भी कहा जाता है, *7,678 मीटर* ऊँचा है और मुख्य शिखर के *उत्तर-पश्चिम* में स्थित है।
  - दूसरा है **चोमो लोंजो**, जो मुख्य शिखर के ठीक *उत्तर* में स्थित है।

विगत अभियान

- *माउंट मकालू* पर प्रथम बार *1954 में एक अमेरिकी* दल द्वारा चढ़ाई का प्रयास किया गया था, लेकिन इसे सफलतापूर्वक *15 मई, 1955* को फ्रांसीसी पर्वतारोही *लियोनेल टेरे* और *जीन कूज़ी* द्वारा फतह किया गया।
- इसे *सच्ची सर्दियों की परिस्थितियों* में कभी भी पूरी तरह नहीं चढ़ा गया है।
  - इसे प्रथम बार *1978 में नेपाली पर्वतारोही आंग चेपाल शेर्पा* ने फतह किया था।

Source :TH

इनसाइडर ट्रेडिंग

समाचार में

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (*SEBI*) ने *प्रणव अडानी* पर *इनसाइडर ट्रेडिंग* का आरोप लगाया है, यह दावा करते हुए कि उन्होंने *अडानी ग्रीन* की *2021 SB एनर्जी अधिग्रहण* से संबंधित मूल्य-संवेदनशील जानकारी अपने *बहनोई* के साथ साझा की।

इनसाइडर ट्रेडिंग

- *इनसाइडर ट्रेडिंग* वह अवैध प्रक्रिया है जिसमें *गैर-प्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी (UPSI)* का उपयोग करके कंपनी के *सिक्योरिटी* में व्यापार किया जाता है।
- इस प्रकार की जानकारी तक पहुँच रखने वाले *कर्मचारी, निदेशक या सहयोगी* इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।
- यह *गुप्त, भौतिक गैर-सार्वजनिक जानकारी* के आधार पर *सिक्योरिटीज* की खरीद-बिक्री से जुड़ा होता है, जो *विश्वास की ड्यूटी* का उल्लंघन करता है।
- इसमें ऐसी जानकारी को साझा करना (*"टिपिंग"*) और इसे प्राप्त करने या दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों द्वारा व्यापार करना भी शामिल है।
- *SEBI* इनसाइडर ट्रेडिंग को नियंत्रित करता है और इसे प्रतिबंधित करता है ताकि *बाजार की निष्पक्षता सुनिश्चित* की जा सके और *निवेशकों की सुरक्षा* की जा सके।

Source :TH

घरेलू संस्थागत निवेशक (DIIs) FPIs से आगे

संदर्भ

- घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने 2025 की मार्च तिमाही में एनएसई-सूचीबद्ध कंपनियों के स्वामित्व में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) को पीछे छोड़ दिया।

परिचय

- DIIs के पास 17.62 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जो दिसंबर 2024 तिमाही में 16.89 प्रतिशत थी।
  - FPIs स्वामित्व 17.22 प्रतिशत रहा।
- प्राइम डेटाबेस द्वारा 2009 में डेटा ट्रैकिंग प्रारंभ करने के बाद से यह प्रथम बार है जब DIIs ने FPIs को पीछे छोड़ दिया है।
- **प्रभाव:** DIIs FPIs निकासी के चरणों के दौरान शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करते हैं, जिससे बाजार में अस्थिरता कम होती है।

घरेलू संस्थागत निवेशक

- इनमें म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियाँ, पेंशन फंड और बैंक जैसी संस्थाएँ शामिल हैं जो घरेलू वित्तीय बाजारों में निवेश करती हैं।
- DIIs भी व्यवस्थित निवेश योजनाओं के माध्यम से खुदरा निवेश को चैनल करते हैं।

विदेशी पोर्टफ़ोलियो निवेश (FPI)

- FPIs में दूसरे देश के निवेशकों द्वारा रखी गई प्रतिभूतियाँ और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ शामिल होती हैं।
- यह निवेशक को किसी कंपनी की परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष स्वामित्व प्रदान नहीं करता है और बाजार की अस्थिरता के आधार पर अपेक्षाकृत तरल होता है।
- FPIs होल्डिंग्स में स्टॉक, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स , ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स , बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड शामिल हो सकते हैं।
- यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से अलग है, जो किसी विदेशी कंपनी या परियोजना में किसी अन्य देश के निवेशक, कंपनी या सरकार द्वारा किया गया स्वामित्व है।

Source: BS

ब्लैक होल बम

समाचार में

- शोधकर्त्ताओं ने प्रथम बार *ब्लैक होल बॉम्ब* की प्रयोगशाला में समकक्ष प्रतिकृति बनाई है, जो 1970 के दशक में भौतिकविदों द्वारा विकसित एक सैद्धांतिक अवधारणा है।

ब्लैक होल बॉम्ब के बारे में

- यह एक सैद्धांतिक तंत्र है, जिसमें *घूमते हुए ब्लैक होल* की *घूर्णन ऊर्जा* को निकाला और प्रवर्धित किया जाता है।
- यह *पेनरोस प्रक्रिया (1971)* पर आधारित है, जिसमें *घूर्णनशील ब्लैक होल* की *एर्गोस्फीयर* में कण *फ्रेम-ड्रैगिंग* के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं।
- **एर्गोस्फीयर** वह क्षेत्र होता है जो *इवेंट हॉराइजन* के बाहर स्थित होता है, जहाँ *फ्रेम-ड्रैगिंग* प्रभाव होता है।
- **ज़ेल्डोविच (1971)** ने इस विचार को *घूर्णनशील, अक्षीय-सममित निकायों* तक विस्तारित किया—और भविष्यवाणी की कि *रेज़ोनेंस कक्ष* में ऊर्जा प्रवर्धन संभव है।

इसे प्रयोगशाला में कैसे अनुकरण किया गया?

- एक *घूर्णनशील एल्यूमिनियम सिलेंडर* को *चुंबकीय कॉइल्स* के अंदर रखा गया, जो *घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र* उत्पन्न कर रही थीं।
- **सिलेंडर ने ब्लैक होल के समकक्ष कार्य किया**, और **चुंबकीय क्षेत्र ने तरंग/कण का प्रतिनिधित्व किया।**
- जब **सिलेंडर चुंबकीय क्षेत्र से तेज़ घूर्णन करने लगा**, तो **चुंबकीय क्षेत्र प्रवर्धित हो गया**, जिससे *सुपररेडियन्स* का अनुकरण हुआ।
- **दर्पण जैसी कॉइल्स ने परावर्तक सीमा** बनाई, जिससे *फीडबैक लूप* उत्पन्न हुआ—जो *"बॉम्ब" प्रभाव* की कुंजी है।

Source: TH

पैंगोलिन

समाचार में

- वैश्विक स्तर पर *पैंगोलिन की तस्करी* 2020 के बाद से तेजी से घट गई है।

पैंगोलिन के बारे में

- *पैंगोलिन* के शरीर पर *केराटिन स्केल* होते हैं, और यह पृथ्वी पर ऐसा एकमात्र स्तनपायी है।
- वे *चींटियों, दीमकों* और *लार्वा* को अपनी *लंबी चिपचिपी जीभ* से खाते हैं।
- खतरा महसूस होने पर, वे *वोल्वेशन* (गेंद के रूप में लपेटने) का उपयोग करके अपनी *कवच जैसी स्केल* के माध्यम से स्वयं को बचाते हैं।
- उन्हें *"इकोसिस्टम इंजीनियर"* माना जाता है क्योंकि वे *मृदा के वातन* और *कीट नियंत्रण* में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- भारतीय पैंगोलिन (**Manis crassicaudata**)**
  - **IUCN स्थिति:** *संकटग्रस्त (Endangered)*
  - **आवास:** भारत में व्यापक रूप से फैला हुआ, लेकिन *शुष्क क्षेत्रों (जैसे राजस्थान), उच्च हिमालय और उत्तर-पूर्वी राज्यों* में नहीं पाया जाता।
  - **अन्य स्थान:** *बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका* में भी पाया जाता है।
- चीनी पैंगोलिन (**Manis pentadactyla**)**
- **IUCN स्थिति:** *गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered)*
- **आवास:** *हिमालय की तराई—पूर्वी नेपाल, भूटान, उत्तरी भारत, उत्तर-पूर्वी बांग्लादेश, दक्षिणी चीन।*

Source: TH

ऑपरेशन हॉक 2025

- **संदर्भ**
  - केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों वाले ऑनलाइन बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क को सफलतापूर्वक समाप्त करने के लिए ऑपरेशन हॉक प्रारंभ किया।
- इससे पहले, सीबीआई ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों वाले ऑनलाइन बाल यौन शोषण मामलों के आरोपियों का पता लगाने के लिए 2021 में ऑपरेशन कार्बन और 2022 में ऑपरेशन मेघ चक्र प्रारंभ किया था।

Source: TH

मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार

समाचार में

- ओलंपियन सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला।

मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार

- इसे भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है और इसका नाम भारतीय हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद (1905-79) के नाम पर रखा गया है।
- इसकी स्थापना 1991-92 में हुई थी और यह चार साल की अवधि में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है।
- विजेताओं को एक पदक, प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार मिलता है।
- एमसी मैरी कॉम, एस. मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, विजेंदर सिंह, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसी दिग्गज खेल हस्तियों को अतीत में यह सर्वोच्च खेल सम्मान मिल चुका है।

मेजर ध्यानचंद

- वह भारतीय हॉकी टीम के स्टार थे, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध से पहले के वर्षों में इस खेल पर अपना दबदबा कायम रखा था।
- उन्होंने 1928, 1932 और 1936 में ओलंपिक खेलों में भारत के लगातार तीन स्वर्ण पदक जीतने में अहम भूमिका निभाई थी।
- खेल और गेंद पर उनका नियंत्रण इतना शानदार था कि उन्हें 'हॉकी विजार्ड' और 'जादूगर' की उपाधियाँ मिलीं।

Source :PIB